MINISTRY OF REHABILITATION

Mr. Speaker: The House will now take up discussion and voting on Demands Nos. 71, 72 and 127 relating to the Ministry of Rehabilitation for which four hours have been allotted.

Seventyeight cut motions have been tabled to these Demands. Hon. Members desirous of moving cut motions may hand over at the Table within 15 minutes the numbers of the selected motions. Hon. Members are already aware of the time-limit for speeches.

DEMAND NO. 71—MINISTRY OF REHABILITATION

Mr. Speaker: Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs. 30,90,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1961, in respect of 'Ministry of Rehabilitation'."

DEMAND NO. 72—EXPENDITURE ON DISPLACED PERSONS AND MINORITIES

Mr. Speaker: Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs. 18,59,16,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1961, in respect of 'Expenditure on Displaced Persons and Minorities'."

DEMAND NO. 127—CAPITAL OUTLAY OF THE MINISTRY OF REHABILITATION

Mr. Speaker: Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs. 20,32,48,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1961, in respect of 'Capital Outlay of the Ministry of Rehabilitation'."

Pandit Thakur Das Bhargava. I would request him to confine his remarks to 20 minutes. We have got only four hours.

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सब से पहले दो छोटे से मामलों की तरफ आनरेबल मिनिस्टर साहब की खास तवज्जह दिलाना चाहता हूं, जो फिल वाक्या शिकायत के तौर पर नहीं, लेकिन उनकी खास तवज्जह की मुस्तहक हैं। अव्वल बात तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हर एक जो हमारे पास डाकुमेंट आता है, उसमें यह लिखा हुआ आता है कि अब यह मिनिस्ट्री जल्दी ही खत्म होने वाली है। इसका पहले से एक साल तो बढ़ गया है और मैं समझता हूं कि एक साल और जरूर बढ़ेगा ही। लेकिन ताहम मुझे यह दिखलाई देता है कि आखिर यह मिनिस्ट्री बहुत ज्यादा देर तक चलेगी नहीं क्योंकि जैसा हम पहले से उम्मीद करते थे, इस मिनिस्ट्री का फर्ज यह है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो रिहैबिलिटेशन का काम खत्म करके हराकरी कर ले। अब मेरी गुजारिश यह है कि जब यह सूरत बनेगी जैसा कि आप रोज देखते हैं, कोई डाकुमेंट पढ़िये, किसी साल की रिपोर्ट पढ़िये, आनरेबल मिनिस्टर साहब हर एक रिपोर्ट में दिखाते हैं कि हमने इतने आदमियों को नौकरियां दिलाईं, हमने इतने आदमियों को रिहैबिलिटेट कर दिया, उनका गेनफुल एम्प्लायमेंट हो गया, सही बात तो यह है कि अगर रिहैबिलिटेशन के कोई माने हैं तो वह दो ही माने हो सकते हैं, एक तो मकान और दूसरा गेनफुल एम्प्लायमेंट। जहां तक उन के क्लेम का सवाल है, उन्होंने इतने आदमियों को गेनफुल एम्प्लायमेंट दिलवाये, इतनी ट्रेनिंग दी, इस के लिये मैं उनको मुबारकबाद देता हूं, लेकिन आज मुझ को जो एक बड़ी फिक्र है, मैं जानता हूं कि आनरेबल मिनिस्टर साहब खुद उस का पूरा इन्तजाम नहीं कर सकते और वह यह है कि जब उनकी मिनिस्ट्री खत्म होगी तो हजारों आदमियों का, जिन में से बहुत से डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं, जिन में बहुत से शेड्यूल्ड

कास्ट्स के लोग हैं, जो कि उनके यहां काम करते रहे हैं, उनका क्या बनेगा। जो लोग आठ-आठ, दस-दस बरस तक अपनी जिन्दगी का सब से अच्छा हिस्सा इस रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट की नौकरी करके, उसकी खिदमत करके, खर्च कर चुके हैं, और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, उनके साथ क्या बीतेगी जिस दिन आनरेबल मिनिस्टर साहब इस मिनिस्ट्री को छोड़ कर या खत्म कर के चले जायेंगे। मैं खुसूसन शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के वास्ते अर्ज करना चाहूंगा। हमारे कांस्टिट्यूशन और हमारी गवर्नमेंट आफ इंडिया के आर्डर्स के मुताबिक शेड्यूल्ड कास्ट्स के वास्ते, उनकी नौकरियों के वास्ते उनके दिल में एक खास फिक्र रहती है, चुनांचे, १६ २।३ नौकरियां आम तौर पर मिनिस्ट्रीज के अन्दर उनके वास्ते रिजर्व्ड हैं। ऐसी सूरत में जब उन में से बहुत से डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं, बहुत से ऐसे हैं जोकि डिस्प्लेस्ड पर्सन्स तो नहीं हैं, लेकिन उनमें भी वर्स हालत में है क्योंकि जो शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं उनकी एकानमिक बैकग्राउंड बहुत ही पुअर है, उन्होंने १०-२० वर्ष तक नौकरियां की हैं, वह बाद में किसी चीज पर **फाल बैक अपान** नहीं कर सकते, उनके पास जमीनें नहीं हैं, कोई बिजिनेस नहीं है, तो इस नौकरी से हटने के बाद उनका क्या बनेगा, यह सवाल आज हमारे सामने आता है। मैं अर्ज करूंगा कि यह सवाल सिर्फ बैकवर्ड क्लासेज का नहीं है, शेड्यूल्ड कास्ट्स का महज नहीं है, हम सब का सवाल है। हालांकि सब लोग और यह लोग भी शायद जानते थे कि कोई न कोई ऐसा दिन आयेगा जब हमें इससे जुदा होना पड़ेगा, लेकिन ताहम हमारी अकल का, हमारी फारसाइट का, यह तकाजा था कि उनमें से जो वीकर सेक्शन्स हैं, उनके वास्ते ऐसी कोशिश करते कि जो यहां से हटते, उनको कोई दूसरी नौकरी मिल जाती। इस लिये मैं अर्ज करूंगा कि अब जब कुछ नोटिसेज आने लगे हैं, और कुछ लोगों को नोटिस दिये गये हैं, वह लोग बहुत फिक्रमन्द हैं। कुछ सबार्डिनेट आफिसेज में नौकर हैं, वह यह समझते हैं कि उनको हटना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनमें जो शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं, उनको सब से आखीर में नोटिस दिये जायें।

दूसरी बात यह अर्ज करना चाहता हूं कि आप महज रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर नहीं हैं, आप गवर्नमेंट आफ इंडिया के मिनिस्टर हैं, आप की डिवाइडेड रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, आप की उतनी ही रिस्पांसिबिलिटी है जितनी किसी और मिनिस्टर को या सारी गवर्नमेंट की है। इस वास्ते आप को यह देखना है कि जिन डिस्प्लेस्ड पर्सन्स को आपने बच्चों की तरह पाला और उनकी जिम्मेदारी उठाई है, उनको कहीं आप खुद डिस्प्लेस करके न डाल दें। कहीं आप के फेल से वह अपने आप डिस्प्लेस न हो जायें। इसलिये आप का फर्ज है कि उनके वास्ते आप आल्टर्नेटिव एम्प्लायमेंट प्रावाइड करें। जहां तक शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों का सवाल है, मुझे कहने में जरा भी ताम्मुल नहीं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया का फर्ज है कि वह शेड्यूल्ड कास्ट्स के आदमियों को जल्द से जल्द अल्टर्नेटिव नौकरी दें। शेड्यूल्ड कास्ट्स के बारे में जो रिपोर्टें आती हैं, उन रिपोर्टों के जो लिखने वाले हैं उन्होंने पिछली रिपोर्ट के अन्दर एक शेड्यूल दिया है, जिसके अन्दर टेम्पोरेरी एम्प्लायीज क्लास ३ और ४ का जिक्र किया गया है। उन्होंने कुछ फिगर्स दिये हैं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया की मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज में कितनी शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिये जगहें हैं और कितनों को नौकरियां मिली हैं और कितनी बाकी हैं। मैं सारी लिस्ट पढ़ कर नहीं सुनाना चाहता, इस किताब में लिस्ट दर्ज है। मैं आप से सिर्फ रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री की बाबत अर्ज करना चाहता हूं। उनके यहां कुल ५४६४ एम्प्लायीज हैं जिनमें से ६१५ शेड्यूल्ड कास्ट्स के प्रपोर्शन के लिहाज से उनको आनी चाहियें थीं, लेकिन कुल २४१ आदमी एम्प्लाय किये गये हैं। इस तरह से ६७४ की कसर बाकी थी। इसी तरह से क्लास ४ के अन्दर जो

[पण्डित ठाकुर दास भार्गव]

टैम्पोरेरी लोग हैं वह कुल १९५८ एम्प्लायीज थे जिनमें से ३२६ उनके हिस्से में आते हैं, लेकिन नौकरी में सिर्फ २३४ आदमी थे। इस तरह से ९२ आदमियों की कसर थी। इस कसर को तो आप छोड़ दीजिये, मुझे कोई शिकायत नहीं है, जो कुछ हुआ वह हुआ, लेकिन मेरी गुजारिश यह है कि जो क्लर्क इस डिपार्टमेंट में १० वर्ष तक नौकरी करने के बाद निकलेंगे, वह ऐसे क्लर्क होंगे जो कि किसी महकमे में या मिनिस्ट्री में बड़ी आसानी से खपाये जा सकेंगे। उनकी जरूरत तो रोज ही रहती है, और जरूरत न भी हो तो भी सर्विस में उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिये। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह फर्ज मेरे जैसे अदना मेम्बर का नहीं है, आप का है, जो कि यहां पर रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर हैं, जिन की उन्होंने इतनी खिदमत की है, और जो कि उनको डिस्प्लेस कर के चले जायेंगे कि आप गवर्नमेंट आफ इंडिया से मनवा कर जायें कि शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को, और जहां तक हो सके सब को, अल्टेंटिव एम्प्लायमेंट दिया ज य, उनको डिस्प्लेस्ड पर्सन्स न बना दिया जाय ताकि आप की आंखों के सामने वह सीन न आयें जिन को आप ने इतने वर्षों तक हटाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप इस पर जरूर गौर फरमायेंगे और अपना फर्ज अव्वलीन समझेंगे कि जिस दिन आप छोड़ कर जायेंगे उस दिन इसको डिस्प्लेस करके न जायें।

अब मैं एक दूसरे मामले की तरफ आप की तवज्जह दिलाना चाहता हूं पेश्तर इसके कि मैं उस मामले पर आऊं जिसका मैं खास तौर पर जिक्र करना चाहता हूं। वह छोटा सा मामला यह है कि पंजाब को तो छोड़ दीजिये एक मिनिट के वास्ते, लेकिन राजस्थान में आपने बहुत से लोगों को, कई हजार फैमिलीज को, बसाया। भरतपुर, अलवर और कई दूसरी जगहों में बसाया। गंगानगर में और दूसरी जगहों में आपने कोशिश की कि उनको कुछ रिहैबिलिटेशन बेनिफिट्स मिलें। मैं इस वक्त इसमें नहीं जाना चाहता कि उनको कितने बेनिफिट्स मिले और उनके साथ क्या सुलूक किया गया। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि जब यह चीजें तकरीबन खत्म हो चुकी हैं तब मैं पुरानी हिस्टरी को दोहराऊं जो कि मैं हमेशा करता रहा हूं। मैं तो यही अर्ज करना चाहता हूं कि आप उनके साथ जेनरासिटी बरतिये। जो कुछ आप कर चुके वह कर चुके। उनके ऊपर अब जो नई मसीबत आई है सिर्फ उस का जिक्र यहां पर करना चाहता हूं। जनाब, हमने १९५४ के कम्पेन्सेशन एक्ट के मुताबिक उनको अलाटमेंट दिये, जिन पंजाब के लोगों के पास हजारों एकड़ जमीन थी उनको आप ने ३९९ एकड़ जमीन दी। राजस्थान के लिये आपने यह रूल बनाया कि ३० एकड़ से ज्यादा किसी आदमी को अलाट नहीं की। मुझ को इसकी शिकायत नहीं है, आखिर आपने ३० एकड़ की सीलिंग बना दी है। लेकिन मुझे जो शिकायत है वह यह है कि बहुत से लोगों ने आज तक उन जमीनों पर कब्जा नहीं किया जो कि उनको अलाटेड हैं, सैकड़ों हजारों लोगों को आपने सनदें भी नहीं दीं जिन को जमीन अलाटेड हैं। इसके सिवा बहुत से ऐसे केसेज हैं जिन को आपने दस-दस एकड़ जमीनें दी थीं, वह अपनी जमीनों पर बठे हैं लेकिन कई हजार ऐसे आदमी हैं जो कई कई सौ एकड़ जमीनें पाकिस्तान में छोड़ आये, उनको आपने १० एकड़, २० एकड़ या अपने हक के मुताबिक ३० एकड़ जमीन दी। लेकिन वह किस तरह दीं। जमीनें एक जगह नहीं थीं। उस इलाके के जो मुसलमान थे राजस्थान के अन्दर वह बड़े छोटे-छोटे काश्तकार थे जो जमीन छोड़ कर गये। आपने यह इवैकुई प्रापर्टी दी। वह छोटी-छोटी जगहें थीं। बहुत सी मुस्तलिफ वाटर कोर्सेज में और मुस्तलिफ चक्स में थीं, मुस्तलिफ गांवों में थीं। उनको हमने यह २-२ और ४-४ एकड़ की जगहें दीं और वह इसलिये कि वे स्कैटर्ड थे। एक तरह आपने

ठीक भी किया। आम तौर से लोग ऐसे नहीं थे जो अपने हाथ से खेती करना चाहते थे या खेती करना जानते थे। उन लोगों को जो आपने जमीनें दीं वह गवर्नमेंट आफ इंडिया के कम्पेंसेशन ऐक्ट सन् १९५४ के मुताबिक दीं। वह सारी जमीन इवैकुई प्रापर्टी थी जो कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया की बनी। दफा १२ की रू से उसको एक्वायर करके उन लोगों को सनदें दीं लेकिन सन् १९५९ में एक उनके ऊपर गोला गिरा बिजली पड़ी। एक ऐक्ट नम्बर ८ आफ १९५९ राजस्थान गवर्नमेंट ने पास किया और मैं समझता हूं कि आप को उस का जरूर इल्म होगा। उस ऐक्ट की रू से सारी एबोलीशन आफ जमींदारी और जनाबवाला सुन कर हैरान होंगे कि एबोलीशन आफ बिस्वेदारी राजस्थान गवर्नमेंट ने खत्म कर दी। अब एक एक इंच जमीन की मिलकियत से राजस्थान की सरकार का सम्बन्ध है। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि जो जमीनें हमारे आनरेबल मिनिस्टर साहब ने उनके हक के तौर पर उन लोगों को दी थीं जिनके कि अन्दर सब लोग काश्त नहीं करते थे जमीन के मालिक बन गये थे अब कइयों को तो सनदें नहीं दी हैं और कइयों को मुआविजा नहीं दिया गया है और बहुत से लोगों को जिन को कि जमीनों का कब्जा दिया था अब सारी उनकी जमीन जब्त हो गई है। मेरे पास वह ऐक्ट मौजूद है जिसकी कि दफा ४ और ५ की रू से उनके हकूक खत्म हो गये और सरकार वहां की मालिक हो गई। मैं अदब से पूछना चाहता हूं कि जो चीज आपने अपने हाथ से दी तो फिर उनकी सनदें भी न दी जायं तो क्या आपके सामने आपके दिये हुए इकरार पर इस तरीके से पानी फिर जायगा और आप चुपचाप बैठे रहेंगे? हमारे यहां के रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर हैं और मैं अदब से उनसे अर्ज करना चाहता हूं कि जिन को आप रिहैबिलिटेट करना चाहते थे, हजारों आदमी जिन को कि आपने जमीनें दीं तो क्या उनका कसूर था कि वे इधर लुट पिट कर आये और आपने मेहरबानी करके उनको जो गुजारे का जरिया मिला था मुआवजे के तौर पर तो क्या वह जरिया गुजारे का आपके सामने छीन लिया जायगा और आपके कानों पर जूं भी नहीं रेंगेगी। यह आपका फर्ज है कि आप उनके रेस्क्यू पर आयें और उनको हैल्प करने की तरकीब मैं आपको बतलाता हूं। उसकी तरकीब यह है कि दफा ४ में लिखा हुआ है कि किसी क्लास आफ केसेज या किसी क्लास आफ लैंड्स को अगर चाहे तो राजस्थान गवर्नमेंट उसको एग्जैम्पट कर सकती है। दफा चार में ऐसा लिखा हुआ है और इस तरकीब से उनको मदद पहुंचाना बड़ा आसान था। पंजाब के अन्दर जहां डिस्प्लेस्ड पर्सन्स को खास रिआयतें दी गईं तो पंजाब में जो सीलिंग दी गई वह लोकल्स से मुख्तलिफ थी और उत्तर प्रदेश में उनको खास रियायतें दी गईं। लेकिन राजस्थान में सन् ५९ के उस ऐक्ट की रू से वह सारे हकूक जब्त कर लिये और उनको एक स्टावेंड् और डैसीच्यूट आदमी बना कर छोड़ दिया। दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आपने इन जमीनों की खुद कीमत लगाई है एक एकड़ के हिसाब से तो जिनको कि आपने जमीनें दी थीं आपका यह फर्ज है कि राजस्थान गवर्नमेंट भले ही कुछ भी न करे लेकिन आप इन को इसके एवज में रकम की सूरत में मुआविजा दें। अब उसके लिये जो आपने हिसाब तय किया है तो वह रकम भी काफी नहीं है क्योंकि आपने उसका हिसाब ४००,४५० रुपया फी एकड़ रखा था जबकि आपके सामने ऐसे इन्सटान्सेज मौजूद थे जिनमें कि एक एकड़ जमीन की कीमत १२०० और १४०० रुपये थी। दूसरी तरकीब यह है कि जब तक मिनिस्ट्री खत्म न हो उसका फर्ज है कि उन लोगों को इसके एवज में रुपया दे अगर राजस्थान गवर्नमेंट उनकी बात नहीं मानती है। अब वैसे तो यह कोई बड़ी प्राबलम नहीं है लेकिन उन लोगों के लिहाज से इस वक्त ऐसा हो गया जैसे

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

कि एक दफे कोई डूबता हुआ आदमी जरा किनारे पर आये और फिर रौ उसको बहा ले गयी । मैं अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि इसके अन्दर खास तौर से आपका फर्ज है कि कोई न कोई कदम उठायें ।

तीसरी बात जिसको कि मैं बहुत जोर के साथ अर्ज करना चाहता हूं और जो मेरे बोलने का असल मकसद है वह मैं जनाब की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं । मैं एक ऐसे इलाके का जिक्र करना चाहता हूं जिसकी कि बाबत मुझे उन भाइयों ने जिनकी कि तरफ से मैं बोल रहा हूं मुझ को बतलाया था । एक मर्तबा आप भी वहां किंग्सवे कैम्प में तशरीफ ले गया था और यह किंग्सवे कैम्प आपका सब से पहला शरणार्थी कैम्प था जहां पर कि यह शरणार्थी भाई आकर टिके थे । किसी वक्त किंग्सवे कैम्प में २५००० कुन्बे होते थे । उस वक्त जो लोग यहां पर आये उनकी कैसी बुरी हालत थी वह मैं इस वक्त बताना नहीं चाहता क्योंकि न उसका मौका है और न महल है । लेकिन मैं अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि आनरेबल मिनिस्टर ने उन में से कुछ लोगों के वास्ते ४०० घर बनाये थे और जिसको कि विजयनगर बोलते हैं । उस विजयनगर के अन्दर उन्होंने ८०००, ८००० रुपये में एक एक मकान बनाया था । ३००० की जमीन थी और बाकी का मकान था । उस मकान के अन्दर दो कमरे हैं । एक लैट्रिन है, एक किचन है और एक बाथरूम है और हदबन्दी की दीवार है । अब इस तरीके से जो उनको मकान बना कर दिये गये तो वे उससे बहुत खुश हैं और इसके अलावा मिनिस्टर साहब ने और भी चीजें बनाईं लेकिन मैं उन चीजों का इस वक्त जिक्र नहीं करना चाहता लेकिन मैं मिनिस्टर साहब को ट्रिब्यूट दिये बगैर नहीं रह सकता । उन्होंने बड़ी कोशिश की और इतने आदमी जो मुसीबत में थे उन के वास्ते मकानात बनाये और उनको वे मकानात दिये। कई सौ करोड़ रुपया हमारी गवर्नमेंट ने विस्थापित लोगों के आराम के वास्ते खर्च किया और मैं समझता हूं कि जितनी मदद उन्होंने की उतनी मदद दुनिया की किसी दूसरी गवर्नमेंट ने न की होगी । मैं उनकी दाद देता हूं । लेकिन यह जो २५००० आदमी अब बैठे हैं और उन २५००० कुनबों के रैमेनेंट्स हैं और जो रीड्स कौलिनी थी और उसके अन्दर जो ओल्ड बैरक्स थे उस में आदमियों को बसाने के वास्ते आपने खास इंतजाम किया । ढाका में उनको जगह दी और वहां मकानात बना कर दे रहे हैं तो क्या मैं अदब से पूछ सकता हूं कि रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर जो इनका पेटर फैम्लियम होता है तो इन बेचारे नेगलेक्टेड बच्चों ने क्या कसूर किया है कि आप संविधान की दफा १४ को भुला कर उनको ऐसी खराब हालत में बेसहारा छोड़ जांय ? एक मौके पर इन ओल्ड बैरक्स में जो लोग रहते थे उनकी बाबत खुद आनरेबल मिनिस्टर साहब ने कहा था कि वे हैल में रहते हैं । लाला अचितराम ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा वे यहां बैठे हैं । उन्होंने भी लिखा कि जैसी बुरी हालत उन्होंने किंग्सवे कम्प में देखी ऐसी बुरी हालत ३६ कौलनीज में कहीं नहीं देखी । अगर कहीं नमूना देखना है किसी हैल का तो किंग्सवे कैम्प को देखा जा सकता है । लोअर मिडिल क्लास के आदमी जो कि ओल्ड बैरेक्स में रहते थे तो बिलकुल हैल में वे लोग रहते थे और ऐसा हैल ऐन दिल्ली के बीच में मौजूद है अब किंग्जवे कैम्प में तो यह हमारे कैप्टिल पर एक बड़ा भारी डिस्ग्रेस है कि ऐसे हालात में हमारे देश की राजधानी में लोग रहते हैं । एक एक कमरे के अन्दर जो १४×१० फीट २ नहीं ३ नहीं ५ नहीं बल्कि १०, १० और १२, १२ लोग रहते हैं और हालत यह है कि वहीं पर नौजवान लड़का रहता है, नौजवान बहू रहती है और वहीं पर लड़के के मां, बाप, बुआ और बहन रहते हैं । यह सारा मकान ३३ गज जमीन पर लगा है । उन के पास पाखाना जाने को अलग

जगह नहीं है और १००, १०० आदमियों के पीछे एक पाखाना है । इसी तरह टैब भी हर एक घर के पास नहीं है और हजार आदमियों के पास एक टैब है । बाथरूम का कोई बंदोबस्त नहीं है । मकानों के पीछे दस फिट चौड़ी गली है जिस में कि वह नौजवान लड़का, बहू, मां, बाप और बच्चे बूढ़े सब सोते हैं । अब अगर कोई बाहर का आदमी यह हालत देखे तो क्या कहेगा और हम तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जायेंगे कि एक ऐसी चीज भी दिल्ली के अन्दर मौजूद है । अगर जनाब मलाहिजा फरमायेंगे तो पायेंगे कि इसके अन्दर कसूर हमारा कतई नहीं है मुझे पता नहीं है कि किस का कसूर है । अब मैं कसूर पर अर्ज करना नहीं चाहता लेकिन ताहम मैं आनरेबल मिनिस्टर साहब से अपील करता हूं कि चाहे किसी का कसूर हो लेकिन जब वे आदमी आप के चार्ज में हैं तो उन को ऐसी बेकसी की हालत में छोड़ कर जो वे जाना चाहते हैं तो यह कहां तक ठीक होगा । मैं ने सुना है कि एक देवता जब कि वे ऊपर आस्मान में जाने लगे तो वे एक कुत्ते को पृथ्वी पर अपने पीछे नहीं छोड़ सके और उसको भी अपने साथ ले जाने का उनका आग्रह था । अब यह २५००० आदमी आपकी जिम्मेदारी हैं और आप इनको इस हालत में छोड़ कर नहीं जा सकते हैं । जिस वक्त यह लोग यहां पर आये थे तो गवर्नमेंट ने यहां पर ८००, ६०० रुपये के टैंट्स लगाये अगले साल परमात्मा की ऐसी मर्जी हुई कि मेंह बरसा और कुछ टैंट्स जल गये । अब टैंट्स जल जाने पर वहां पर थोड़े से मकानात बनाये जिनकी कि बाबत मैं अर्ज करूं कि शुरू में तो यह मकानात तीन साल के वास्ते बनाये गये थे अब उनकी मियाद तीन साल की जगह पांच साल कर दी है । लेकिन अब उनको दस साल बीत जाने से उनकी जिन्दगी खतम हो चुकी है, इस के अन्दर बहुत से लोगों को बसाया गया । विजय-नगर और दूसरी कौलनीज शरणार्थियों के लिए बनाई और उन्होंने २७०० घर इनके वास्ते बनाये । सन् १९५८ में जब उन्होंने दरख्वास्त दी थी तो रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री की तरफ से चीफ कमिश्नर ने एक ऐश्योरेंस दिया था और उस ऐश्योरेंस की कापी मेरे पास मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा था कि यह मिनिस्ट्री आपके वास्ते परमानेंट मकानात बनाना चाहती है और जो आपके डर और खदसात हों उनको दूर कर लो । आप के साथ बेइंसाफी नहीं होगी । सन् १९५८ में यह चीज आनरेबुल चीफ कमिश्नर ने हमारी इस मिनिस्ट्री की तरफ से वहां पर कही और शाया की । उसके कहने के बाद यह झगड़ा हो गया और श्री मोहन लाल जो कि गालिबन उस वक्त मिनिस्टर थे, उन्होंने एक रुपया जो कि रोज उनको खाने का मिलता था वह भी बन्द कर दिया था और उसके बन्द करने पर बहुत झगड़ा हुआ । उन्होंने कह दिया कि तुम लोग घबराओं मत यह खाने का एक रुपया बन्द कर दिया गया है लेकिन बाकी सारी रियायतें तुम्हें पहले की तरह मिलेंगी और तुम से इन मकानों का कोई किराया नहीं लिया जायगा । बतई किराया नहीं लिया जायगा यह भी उस के अन्दर मौजूद है । मैं जनाब को दिखलाउंगा कि उनसे उन मकानों का किराया भी लिया गया उनकी खाल से खींचा गया एक्सटोट करके और इस बेदर्दी से लिया गया जिसका कि मैं आपको जिक्र करके सुनाना चाहता हूं । सन् १९४९ में यह वाकया हुआ और फिर जनाबवाला इसको देखने के वास्ते फिलवाकया इन्होंने क्या किया । मैं जनाब की खिदमत में दो नक्शे पेश करना चाहता हूं और इसमें मिनिस्ट्री ने २००, २०० गज के प्लाट्स बना कर नक्शे बनाये । इन नक्शों की रू से २००, २०० गज के प्लाट्स दे कर यहां पर मकानात बनाये जाने थे । यह आउटरम और हडसन के नक्शे में बाजाब्ता तौर पर इनकी नकूल हासिल करके लाया हूं । अब मिनिस्ट्री का वायदा था कि २००, २०० गज के प्लाट्स देंगे और

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

उनके वास्ते मकान बनायेंगे और उन मकानों को पक्का बनायेंगे और जैसे और जगहें बख्शी हैं यहां भी बना कर तुम्हें देंगे। लेकिन हुआ क्या? १६४६ के अन्दर जब शक्ल बनी तो जनाबवाला १० रुपया माहाना किराया, बरखिलाफ उस इकरार के और वायदे के, हमसे चार्ज किया गया। दस रुपया माहाना किराया चार्ज किया गया।

श्री नर्भन : यह कम किया गया था।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं अभी आता हूं घबराइये नहीं। फिर उसके बाद सन् ५८ में जब उन्होंने आनरेबुल होम मिनिस्टर साहब को दरख्वास्तें दीं और खन्ना जी को भी कहा तो जैसे कि खन्ना जी की आदत है उन्होंने उनकी दरख्वास्तों पर हमदर्दी से गौर किया। और जहां तक उनके रिसोर्सेज थे वह बराबर कहते रहे कि तुम्हारे वास्ते मकानात वगैरह सब कुछ बनाएंगे लेकिन ऐसा मालूम होता है कि सन् १६५८ में या तो मिनिस्ट्री का रुपया खत्म हो गया या कोई और बात हुई कि सन् १६५८ में उन्होंने यह सोचा कि ये जो सारे मकानात बने हुए हैं इनको इनके क्लेम्स में काट लो और ये मकान इनके सिर मढ़ दो, और किस तरह ये मकान इनके सिर मढ़े गए। इनको लेने को कौन राजी हो सकता था क्योंकि ये मकान तीन साल के लिए बने थे वह उम्र इनकी खत्म हो चुकी थी और उसको पांच साल तक बढ़ाया गया था, वह मुद्दत भी खत्म हो चुकी थी। कोई शख्स इनको लेने को तैयार नहीं होता था। लेकिन उनको धमकियां दी गयीं कि तुम को मकान से निकाल दिया जाएगा, तुम्हारा बैग एंड बैगेज फेंक दिया जाएगा और इन मकानों को नीलाम कर दिया जायगा। चुनांचे इन मकानों को यूनीलेटरली क्लेम्स में एडजस्ट किया गया। हम इसके लिए कभी रजामन्द नहीं थे। लेकिन ये सारे मकान हमारे सिर मढ़ दिए गए और १८०० इनकी कीमत लगायी गयी और जिन्होंने यह कीमत अदा कर दी उनको कह दिया गया कि ये मकान तुम्हारे हैं। मैं खन्ना साहब का शुक्रगुजार हूं कि जब उनको पता लगा कि १८०० कीमत ज्यादा है, तो उन्होंने हिसाब लगा कर इनका किराया दस रुपए से साढ़े ६ रुपए कर दिया और इन की कीमत १८०० से १५०० कर दी। लेकिन १५०० तो क्या थे मकान ५०० के भी नहीं हैं। इनमें ए०सी० शीट्स लगी है और ये इतने कमजोर है कि जब बरसात या आंधी आती है तो लोग डरते हैं कि उनके ऊपर न गिर जाएं। बहुत दफा दरख्वास्त दी गयी कि ये मकान रहने लायक नहीं है, न उनके साथ किचन है, न कुछ और है, उसी में किचिन है, उसी में बीमारी में आदमी व बच्चे पखाना जाते हैं उसी में लेटरिन है, उसी में सब कुछ है। सच्चे माइनों में यह मकानात हेल का नमूना हैं।

अब मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी डिमांड क्या है। मैं अनरीजनेबिल नहीं हूं। मैं नहीं चाहता कि हम मिनिस्ट्री की मेहरबानी का नाजायज फायदा उठायें। जनाब वाला, शिकायत यह थी कि जमीन नहीं है। लेकिन आज ११६ एकड़ जमीन के अन्दर ये मकानात आउटरम और हडसन में बने हुए हैं। और जैसाकि इन नक्शों में दर्ज है और जो खुद मिनिस्टर साहब ने भी माना है, वहां ११६-७५ एकड़ जमीन पड़ी हुई है। मैं यह नहीं चाहता कि जिस तरह से आप ने औरों को आठ आठ हजार में मकान बना कर दिये उसी तरह से हम को भी दें। मेरी तो निहायत अदब से गुजारिश है कि आप सिर्फ इतना ही इन्तिजाम कर दें कि १२५ गज जमीन के प्लाट बना कर हम को दें और उस पर हमारे लिये मकान बना दें। और ये मकान दो दो हजार में बन सकते हैं। मैं यह नहीं चाहता कि मैं इन मकानों की कीमत न दूं। या जमीन की कीमत न दूं। मैं जमीन की भी कीमत देना चाहता हूं और मकान की कीमत भी देना चाहता हूं और आप को पांच पर सेंट इंटेरेस्ट भी देने को तैयार

हूं । यह मुझ को उन लोगों ने कहने की इजाजत दी है जिन के बारे में कि मैं अर्ज कर रहा हूं । उस जमीन में ये २७०० मकान बआसानी बन सकते हैं और ३० पर सेंट जमीन सड़कों वगैरह के लिये भी मिल सकती हैं इन ११६–७५ एकड़ में । गवर्नमेंट जो हम से १४·०५ रुपया के हिसाब से डेवेलपमेंट का चार्ज करना चाहती है वह भी हम देंगे । इस का नतीजा यह होगा कि गवर्नमेंट को इन २७०० मकानों को बनाने पर ५४ लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा । जमीन की कीमत करीब ४६ लाख के है । उस में से ४४ लाख आप हमारे क्लेम्स में से मुजरा कर चुके हैं । इस तरह से अगर जमीन की कीमत को छोड़ कर देखें तो आप को १०–१५ लाख रुपया खर्च करना होगा । वह जमीन तो अभी भी उन के पास है और आप के किसी काम की नहीं है । आप यह समझें कि हम ने यह जमीन रिहैबिलिटेशन के लिये दान कर दी । इस के अलावा जो आप का १०–१२ लाख रुपया खर्च हो उस को आप हम से ईजी इंस्टालमेंट्स में वसूल कर लें और पांच फीसदी सूद भी ले लें ।

शायद यह कहा जाय कि अब यह इस मिनिस्ट्री का काम नहीं है । लेकिन मैं अदब से अर्ज करूंगा कि आप चाहे आसमान में भी चले जायें, लोग वहां भी आप का पल्ला पकड़े रहेंगे । आप का यह फर्ज है, गवर्नमेंट का यह फर्ज है । मैं अदब से पूछना चाहता हूं कि क्यों करोड़ों रुपया स्लम्स पर खर्च किया जाता है । यह स्लम किस ने बनाये । ये स्लम गवर्नमेंट की नाक के नीचे और प्राइम मिनिस्टर की नाक की नीचे आप की मेहरबानी से बने हैं क्योंकि आप के पास रुपया खत्म हो गया था । आप ने और जगह आलीशान कालोनीज बनायीं, न्यू विजय नगर बनाया और भी इमारतें बनायीं, लेकिन इन २७०० मकानों के लिये ही क्या हो गया । इन को आप बना सकते थे और अब बना सकते हैं । मैं अदब से अर्ज करूंगा कि आप को इस काम को छोड़ कर नहीं जाना चाहिये । अगर किसी आदमी के बड़े बड़े बच्चे होते हैं और दो तीन नाबालिग बच्चे भी होते हैं तो वह जो बिल करता है उस में उन नाबालिगों की एजूकेशन के लिए, शादी ब्याह वगैरह के लिये प्रावीजन रखता है । इसी तरह से आप अब रेड्डी साहब को बिल कर रहे हैं तो उन को कहते जाइये कि यह काम आप के जिम्मे है । और इस के लिये १०–१५ लाख रुपया निकालिए । यह ज्यादा रुपये का मामला नहीं है । लेकिन यह २५,००० आदमियों का सवाल है । यह काम उन के जिम्मे डालिए । मैं तो चाहता हूं कि आप इस काम को खुद कर के जायें, किसी पर छोड़ कर न जायें और यह न सोचें कि बला टल गयी । जो रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर होता है उस का काम उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकता जब तक कि पूरी तरह से रिहैबिलिटेशन न हो जाय और उस को उस काम को आधा छोड़ कर जाने का कोई हक नहीं है । अभी बहुत से मामले बाकी हैं जिन को आप ने पूरा नहीं किया है । मैं नहीं समझता कि आप क्यों जाना चाहते हैं, न मालूम कोई गवर्नरी आप के लिये खाली है या क्या बात है । आप ने इस गवर्नमेंट का इस काम पर ३०० करोड़ रुपया खर्च किया है, इसलिये आप को इस काम को अधूरा छोड़ कर नहीं जाना चाहिये । सिर्फ यह २५,००० आदमियों का ही सवाल नहीं है, और भी बहुत से मामले हैं जिन को आप को मुकम्मल कर के जाना चाहिये । मैं आप की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि आप इन २५,००० आदमियों की हालत को देखें ।

The Minister of Rehabilitation and Minority Affairs (Shri Mehr Chand Khanna): There is only one personal explanation I want to give. I have not been offered any job anywhere whether as a Governor or as an Ambassador.

मैं यहां पर भार्गव साहब की बात सुनता हूं तो कलकत्ते चला जाता हूं और वहां वालों

[Shri Mehr Chand Khanna]

की बात सुनता हूं तो यहां चला आता हूं, मुझे कोई आफर नहीं है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मुझे इस का पता नहीं था । लेकिन मैं तो जानता हूं कि अगर गवर्नमेंट आप से पूछे कि आप गवर्नरी पर जाना चाहते हैं या इस काम को करना चाहते हैं, तो आप इस काम को करना पसन्द करेंगे । मैं तो चाहता हूं कि आप का दरजा ऊंचे से ऊंचा हो । लेकिन मैं ने जो बात कही है वह बैड सेंस में नहीं कही है और जिस सेंस में मैं ने कही है उसी सेंस में उसे आप लें । लेकिन मेरी गुजारिश यह है कि आप कहीं पर भी जाएं इन को छोड़ कर न जायें, इन के केसेज को तै कर के जायें ।

मैं जानता हूं कि दंडकारण्य की स्कीम को पूरा करने की आप को बड़ी एंजाइटी है ।

Mr. Speaker: Hon'ble Member should now conclude. I have already given him 30 minutes. He may take two or three minutes more.

Pandit Thakur Das Bhargava: I conclude.

Mr. Speaker: Shri Prabhat Kar. *(Interruptions.)*

Shri Prabhat Kar: I will speak tomorrow.

Mr. Speaker: I would not call him tomorrow. Hon. Members cannot dictate to me when and how I should call. Some Members write to me saying, "Call me before lunch or after lunch; the train is in the station" and so on. I am really surprised.

Shri T. B. Vittal Rao: We have revised the decision and we have put in the name of Shri H. N. Mukerjee to speak on behalf of our group. I am sorry we did not communicate it to you.

Mr. Speaker: Where is that hon. Member now? I have got a letter only from Shrimati Renu Chakravartty. Both of them are not here. Shall I reserve the whole of tomorrow and day after tomorrow for these hon. Members?

Shri D. C. Sharma *rose—*

Mr. Speaker: Shri D. C. Sharma.

Shri D. C. Sharma: Mr. Speaker, Sir, I rise to speak today with mixed feelings. It is because our Rehabilitation Minister threatens to die by half. I can think of a man who goes for complete death, a man who goes in for complete suicide, a man who goes for complete renunciation, but our Rehabilitation Minister wants to survive himself to the extent of one half of himself. That is to say, he thinks that the work of the Rehabilitation Ministry, so far as the western half is concerned, is completed and therefore like a *sadhu* he should take to *vanaprasthashram* from now. When the work of the eastern half is completed, I am sure he will take to complete *sanyas*.

I ask, with this background, has the work been completed? Has the work in the western half been finished? The difficulty with the Rehabilitation Ministry is that it lives more on statistics and on maps and graphs, but not things which take into consideration human feelings, human sentiment, human difficulties and human problems. It looks upon the whole thing from an impersonal angle rather than from a personal angle. It looks at the whole thing from an arithmetic angle rather than from a human angle. When you look at this human problem of rehabilitation from the needs of the refugees who have come from West Pakistan or East Pakistan, the work is not completed.

While this Ministry is completing one aspect of the work it is also creating another problem along with that. There are some insects....

Mr. Speaker: How can he answer this general thing? What are the specific points of the hon. Member?

Shri D. C. Sharma: I am coming to that.

Mr. Speaker: By that time his time would be over.

Shri D. C. Sharma: There are certain things which go on multiplying themselves. For instance, you remember, Sir, about 7,000 employees of the Rehabilitation Ministry are going to be retrenched. What do you think of a Ministry which leaves behind the trial of 7,000 young unemployed persons? The other day we were told that some of the officers are also going. I am glad that the officers also will be retrenched. Formerly, we used to have poor clerks, poor chaprasis there who used to be retrenched. It redounds to the glory of the Rehabilitation Minister that he has succeeded in retrenching some officers also. But what do you think of this Ministry.

Mr. Speaker: Has he any idea as to how many out of these are refugees?

Shri Mehr Chand Khanna: I could not give the figure off-hand but possibly a preponderance of them would be displaced persons. But I am not sure.

Shri D. C. Sharma: While it is going to wind itself up, it is also thinking of winding up the homes of several thousand employees. I must say to you in all honesty, in all humility, that you were kind enough to constitute a committee, an *ad hoc* committee of Members of Parliament, who should try and see that these poor retrenched employees do not suffer inordinately. I also know that through your good services, through the kindness of your mind, there has been some clearing of the jungle, a little clearing of the jungle. But I would ask you: why is it that these notices were served on these persons one month or two months or three months in advance? Why is it that the Ministry did not have a forecast of what was to come? Why is it that the Ministry did not think of these things in advance of the doomsday? So, how can you think of winding up this Ministry when it is going to gamble with the careers of 7,000 of your employees.

Again, my guru, Pandit Thakur Das Bhargava, referred to retrenched persons who belong to Scheduled Castes. I know that we must give our best to the Scheduled Castes, but Scheduled Castes are not scheduled clerks. I do think that those people should be integrated into an earning group of our society and unless that is done, I think this Ministry has no right to proclaim its suicide.

Shri Palaniyandy: That too after 13 years of service.

Shri D. C. Sharma: I have been saying all these days that this Ministry has so many loose ends, so far as its work is concerned. It has left so many things undone. Its completeness lies in incompleteness. Its work is finished, but it is finished in an unfinished manner.

Mr. Speaker: Why not the hon. Member suggest some remedies?

Shri D. C. Sharma: I am going to suggest that. Either the Government of India should appoint an assessment committee of the work done by this Ministry or, if the Government of India is not going to do that, I think you, Mr. Speaker, should appoint a committee, an *ad hoc* committee of the Members of Parliament to see how far the work in the western section of this Rehabilitation Ministry has been completed.

Shri C. K. Bhattacharya (West Dinajpur): Also the eastern section.

Shri D. C. Sharma: I will come to that also. They should not be impatient.

That is the first thing that I would say. Something has been stated about the Kingsway camp people. I wish that every Member of this Parliament, whatever party he may

[Shri D. C. Sharma]

belong to, Congress or non-Congress, Socialist or non-Socialist, whatever his party may be, should visit the Kingsway refugee camp; I should not say 'visit', I should call it a pilgrimage to the temple of Daridranarayana, because the most unfortunate specimen of our refugees are left there.

In what condition do they live there? It is not possible for me to describe that. They live in appalling, dehumanizing conditions there. I have been there and I tell you the condition of those refugees has haunted me all these days and nights. I am a very thick-skinned man, a hardened man. I would not have lived all these years if I had not been like that. But I felt unhappy and I still feel unhappy when I think of those Kingsway Camp refugees. Unless they are properly rehabilitated, I think the hon. Minister will be doing injustice to himself, to the Government of India and to the cause of the refugees by saying that the work has been completed. I would ask every hon. Member of Parliament to go there. If they go there I am sure they will bear me out that while describing the condition of those refugees I have indulged not in overstatement but in understatement.

Then I would say that this Ministry has been very good in giving grants to educational institutions. I have not been able to understand the principles which this Ministry has evolved in giving those grants. Some refugee institutions have been given grants which are very very high. I do not know what principles they have followed. At least I fail to understand them. For instance, some institutions which were not uprooted from Western Punjab have been given sums of a lakh of rupees or something more and some institutions which have come from West Punjab after having been uprooted have not been given that much. I have therefore to say that the hon. Minister should tell us as to what principles have guided him in giving grants to the uprooted institutions or in giving grants to these institutions whether uprooted or not uprooted. I would like to have from him a very firm answer to this question. It is because whenever I go to the Punjab people tell me that these grants are being given in a way which they cannot understand. I do not want to put it very strongly. So this is another point that I want to make.

Again, I would say that there is another class of refugees that we have got in our country now. We have recognised them. Formerly we did not recognise them. They are the refugees from the Pakistan held area of Jammu and Kashmir. We have now tried to do something for them. But I would say to the hon. Minister that these persons are as unfortunate as the persons from East Pakistan. These persons cannot give certificates of their land. How can they get certificates of their lands? These persons cannot give you an inventory of the property that they have left behind. They cannot do so. It is because their territory, their home is forbidden for them. I would therefore say that the Ministry should do something in the matter and revise the scale of grants and loans and subsidies so far as these refugees from Kashmir are concerned.

Mr. Speaker: The hon. Member's time is up.

Shri D. C. Sharma: Now I shall take two minutes more. I think I have not spoken already for 15 minutes.

Mr. Speaker: I have no objection to giving him two minutes more. But let him not say that he has not taken 15 minutes.

Shri D. C. Sharma: I was submitting very respectfully that one of the most difficult duties laid upon this hon. Minister and one of the duties which he was in a better position to discharge than anybody else was that

he should be able to settle the outstanding claims with regard to the refugees beween India and Pakistan. That was one thing. Our Minister has gone there, and he has many friends there.

Shri Mehr Chand Khanna: One has been assassinated, and the other has gone to England.

Shri D. C. Sharma: I am sorry for him, but I was saying he has so many friends there. He goes there, and I tell you he always come back empty-handed, almost empty-handed. What about the Immovable Property Agreement? It has worked, but it has worked in a way which shows that this has been treated as a joke, I am sorry to say. Then there are claims for pensions provident fund of displaced persons. What has happened to them? I ask the Minister what has been done with regard to the transfer of insurance policies. I ask the Minister what has been done about the verification of the services and emoluments of displaced persons for the purpose of calculation of pensions. So many persons are there who have not been able to draw their pensions up to this time because the facts are not available. What has happened to the contractors' claims? What has happened with regard to the recovery of co-operative societies' dues? In my former constituency there is a very flourishing co-operative society, and they have lost so many lakhs of rupees on account of that, they have not got any books.

What effort has the Minister made so far as the solution of our disputes with Pakistan is concerned? When Pakistan has been in a tough mood, our Minister has gone there; when Pakistan has been in a friendly mood, our Minister has gone to Calcutta or stayed in Delhi. I think our Minister should have struck the iron when it was hot. When the relations between the two countries were improving, he should have done something, but he did not do anything.

Therefore, I say that this aspect of the work of this Ministry is something which makes me very unhappy. With his diplomatic ways, with his fine methods, with his charming manners, with his fine powers of speech, with his Northwest Frontier background, with his friendships in Pakistan, this Minister should have been able to do something with Pakistan, but I contemplate his record here as in other matters with a great deal of unhappiness.

This Ministry has done many good things, I do not deny it, but I say there are also many things which it ought to do, which have not yet been done, and the Minister goes about saying he is going to wind up the western part of his Ministry. I cannot understand why he is going to wind it up. Does he mean to say that he will paralyse his right hand while his left hand will be working? No, I want both his hands should be working together. The western and eastern sections should be working together. The emphasis may be on the eastern part now than on the western part, but you cannot go to the people and say that you have finished your work.

In this world, nobody is able to finish his work. I will conclude my remarks by quoting a line from Robert Browning. He says in one place:

> "Compare the petty done with the undone vast."

That is the life of all of us, but so far as this Ministry is concerned, it is a case of almost nothing done and undone vast, and yet this hon. Minister goes about saying that he is going to wind up this Ministry. I tell you we will not let this Ministry to be wound up till every refugee from West Pakistan or East Pakistan....

Ch. Ranbir Singh: Went back.

Shri D. C. Sharma: ....is settled properly. This man from Hariyana wants them to go back. And if he is a land holder, he has a land, he has

[Shri D. C. Sharma]

a home, he has some source of gainful employment, his children are able to receive education and he has a future. He is not always saying to himself, "I was like this there. What am I now?". No. He will say to himself, "I was like this in West Pakistan, I was like this in East Pakistan but I am much better now".

That is the attitude from which the hon. Minister should approach his work and if he does that, I am sure he will earn the gratitude not only of the refugees but also the gratitude of the 40 crores of people. After all, the refugees are a part and parcel of the Indian population and, therefore, I think by putting them stable on social, economic and other grounds he will be doing something which will be very useful.

Mr. Speaker: The hon. Member's time is up.

Shri D. C. Sharma: I wanted to say something about Dandakaranya. But you have rung the bell and I take my seat.

Shri C. K. Bhattacharya: Mr. Speaker, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to take part in this debate. In fact, I shall take the cue from my hon. friend Shri D. C. Sharma who preceded me.

Before doing that, I would like to offer the hon. Minister an opportunity to clarify a difficulty which we have been facing in Bengal since a dispute arose between the State Government and the Union Ministry of Rehabilitation over the fate of the refugees and over the sending of the refugees to Dandakaranya.

A few days back in the Bengal Legislative Assembly there was a discussion over this question and in the course of that discussion one Member from the Opposition, Shri Siddarth Ray put before the Assembly confidential minutes of what happened between the Union Minister of Rehabilitation and the State Minister of Rehabilitation. He did not disclose from where he got those minutes. On the side of the Government, Shri Shankar Das Banerjee who was the ex-Speaker, himself produced those very minutes. He said, "I have got those minutes from the Government and I challenge Shri Ray to state from where he got them". To that question of Shri Banerjee, Shri Ray did not give any reply. But after that there has been a publication in a paper and I believe the hon. Minister knows that paper very well, a Bengali Daily of Calcutta in which it has been categorically stated that those confidential minutes passed to Shri Ray from the Union Minister of Rehabilitation.

Shri Mehr Chand Khanna: Before the hon. Member proceeds any further I want to clarify this and I am prepared to satisfy my hon. friend that I passed out nothing. I may also clarify the position here that when meetings are held.....

Shri Aurobindo Ghosal: The hon. Minister may clarify it later.

Mr. Speaker: Let him do it now.

Shri Mehr Chand Khanna: When meetings are held between the Government of India and the State Government, whether at the Minister's level or at the Secretary's level, these minutes are recorded. Then copies—not one, two, three or four—in very large number are distributed all over, I mean, within the Government of India and the State Government. Now, I have an office in Delhi. If the meeting is held which has a bearing between Bengal and Delhi then copies will be made out and five of them will be sent to my office here. If a meeting is held between me and the State Government, ten copies, if I mistake not—maybe five, are made out, which are sent in addition, to the officers who attended these meetings. So, these documents are not documents which can be called confidential or secret. These are

minutes of meetings held between Ministers and Secretaries, which are available both in the State Governments and in the Government of India, and might also be available in Dandakaranya and other places, because if I have to keep the other departments of this Ministry posted in all these things, then they must have them.

19 hrs.

Shri Aurobindo Ghosal: How could it go to Mr. Roy?

Shri Mehr Chand Khanna: I can only tell him that he belongs to the Opposition. He had never been a friend of Shri Mehr Chand Khanna or Shri P. C. Sen or Dr. B. C. Roy. He was a man who resigned on a certain issue from the Cabinet of Dr. B. C. Roy. How he got them, it is for Shri Ghosal to find out, and I hardly know that gentleman.

Shri Aurobindo Ghosal: But the papers accuse you and say that you briefed him to save your face from the Congress.

Shri Mehr Chand Khanna: My misfortune has been that whatever is said in a particular paper, Bengali *vis-a-vis* non-Bengali is generally accepted.

Shri S. M. Banerjee: No, that is a charge against the hon. Minister. How can he deny that?

Shri Tangamani: Anyway, it has appeared in the papers, and a reply has to be given.

Mr. Speaker: Leave that alone. Here is the answer of the hon. Minister.

Shri C. K. Bhattacharya: In this particular case, it has been rather unfortunate that the hon. Minister has brought in the question of Bengali *versus* non-Bengali. The question was this. How could confidential minutes or minutes which were considered to be confidential leak out to an Opposition Member; while Members on the side of the Congress were complaining that they did not get those minutes, how could they go to the Opposition? If the minutes were meant for open circulation, I believe the Members on the side of the Congress would have been posted with them. But, I believe that the hon. Minister may remember that Dr. Maitreyi Bose made this specific complaint in the Assembly that she, belonging to the Congress Party had not got those minutes, and yet, on the Opposition side, Mr. S. Roy had come forward and brought those minutes in the face of the Government .

Shri Mehr Chand Khanna: May I intervene once again? I make a statement as a Minister in this House, and I would very much expect that my version should be accepted.

I wish to tell the House one thing more that this episode is a very unfortunate one. But a few days before when the debate was going on in that very House, about rehabilitation in West Bengal and Dandakaranya, a Deputy Minister of the West Bengal Government read out extracts from a letter alleged to have been written by Mr. Profulla Sen to me. That letter was read out in the West Bengal Assembly. It is for Shri Bhattacharya to find out who gave that letter to the Deputy Minister—and it is the Deputy Minister of Rehabilitation—I would say that that was not a confidential letter; that was a letter written by her Ministry to me; and extracts from that letter were read out in that House.

Then, on the second debate, extracts from records of meetings which have been held between us and the State Governments were read out by some Opposition Members. It is most unfortunate. I accept it. But it was not I who gave any minutes to the Deputy Minister. I would like Shri C. K. Bhattacharya to enlighten the House on one point. Does he also suspect me that the copy of the letter alleged to have been written to me by Mr. Profulla Sen, which was read out

[Shri Mehr Chand Khanna]

by the Deputy Minister of Rehabilitation was also given by me to her?

An Hon. Member: Yes.

Mr. Speaker: The hon. Member Shri C. K. Bhattacharya may continue on the next day.

The hon. Members may now move their cut motions relating to the Demands under the Ministry of Rehabilitation subject to their being otherwise admissible.

Failure to rehabilitate displaced persons in Dandakaranya

Shri S. M. Banerjee: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Rehabilitation' be reduced to Re. 1." (1541)

Failure to give alternative employment to the retrenched employees of the Rehabilitation Ministry

Shri S. M. Banerjee: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Rehabilitation' be reduced to Re. 1." (1542).

Question of selling plots of land on which the displaced shopkeepers in Ulhasnagar have constructed their shops

Shri Parulekar: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Rehabilitation' be reduced by Rs. 100." (1567).

Question of recovering ground rent from 1949 onwards from displaced shopkeepers for shops constructed by them in Ulhasnagar

Shri Parulekar: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Rehabilitation' be reduced by Rs. 100." (1568).

High prices demanded from non-claimant displaced persons for purchasing tenements in Ulhasnagar allotted to them

Shri Parulekar: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Rehabilitation' be reduced by Rs. 100." (1569).

Decision to recover arrears of rent since 1949 from the non-claimant displaced persons in Ulhasnagar for tenements occupied by them

Shri Parulekar: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Rehabilitation' be reduced by Rs. 100." (1570).

Policy of selling tenements in Ulhasnagar to displaced persons

Shri Parulekar: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Rehabilitation' be reduced by Rs. 100." (1571).

Question of selling plots of land on which the displaced shopkeepers in Chambur and Ulhasnagar have constructed their shops

Shri Assar: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Rehabilitation' be reduced by Rs. 100." (1760).

Need to stop recovery of ground rent from 1949 onwards from displaced shopkeepers for shops constructed by them in Chambur and Ulhasnagar

Shri Assar: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Rehabilitation' be reduced by Rs. 100." (1761).

Prices demanded from non-claimant displaced persons for purchasing tenements allotted to them in Chambur and Ulhasnagar

Shri Assar: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Rehabilitation' be reduced by Rs. 100." (1762).

Need to revise decision to recover arrears of rent since 1949 from the non-claimant displaced persons in Chambur and Ulhasnagar for tenements occupied by them

Shri Assar: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Rehabilitation' be reduced by Rs. 100." (1763).

Need to change policy regarding selling of tenements in Chambur and Ulhasnagar to displaced persons

Shri Assar: I beg to move:

"That the demand under the head **'Ministry of Rehabilitation'** be reduced by Rs. 100." (1764).

Failure to provide proper education facilities to displaced persons

Shri Assar: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Rehabilitation' be reduced by Rs. 100." (1765).

Failure of the Dandakaranya Scheme

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head 'Expenditure on Displaced Persons and Minorities' be reduced to Re. 1." (1681).

Failure in the rehabilitation of displaced persons in West Bengal

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head 'Expenditure on Displaced Persons and Minorities' be reduced to Re. 1." (1682).

Need to treat Scheduled Castes displaced persons on equal footing with other displaced persons

Shri B. K. Gaikwad: I beg to move:

"That the demand under the head 'Expenditure on Displaced Persons and Minorities' be reduced by Rs. 100." (290).

Need to abolish separate camps for Scheduled Castes displaced persons

Shri B. K. Gaikwad: I beg to move:

"That the demand under the head 'Expenditure on Displaced Persons and Minorities' be reduced by Rs. 100." (291).

Need for providing employment to displaced persons in Taherpur colony

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the demand under the head 'Expenditure on Displaced Persons and Minorities' be reduced by Rs. 100." (1669).

Need for establishing industries in Taherpur Colony

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the demand under the head 'Expenditure on Displaced Persons and Minorities' be reduced by Rs. 100." (1670).

Need for immediate financial help to displaced persons in Taherpur Colony.

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the demand under the head 'Expenditure on Displaced Persons and Minorities' be reduced by Rs. 100" (1671).

Failure to establish industry in Gayeshpur Colony.

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the demand under the head 'Expenditure on Displaced Persons and Minorities' be reduced by Rs. 100." (1672).

Failure to provide employment to displaced persons trained in Training Centre in Gayeshpur.

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the demand under the head 'Expenditure on Displaced Persons and Minorities' be reduced by Rs. 100." (1673).

Failure to provide employment to displaced persons trained in Khoshbasmahalla Training Centre

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the demand under the head'Expenditure on Displaced Persons and Minorities' be reduced by Rs. 100." (1674).

Failure to provide medical facilities in various camps for displaced persons in West Bengal

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the demand under the head 'Expenditure on Displaced Persons and Minorities' be reduced by Rs. 100." (1675).

Need for expeditious sanction of Bynanama Schemes

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Rehabilitation' be reduced by Rs. 100." (1676)

Need for regularising squatters' Colonies expeditiously

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Rehabilitation' be reduced by Rs. 100." (1677)

Failure to provide proper medical facilities for displaced persons suffering from T.B.

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Rehabilitation' be reduced by Rs. 100." (1678)

Procedure of granting business loan

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Rehabilitation' be reduced by Rs. 100." (1679)

Procedure for giving agricultural loans to displaced persons

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Rehabilitation' be reduced by Rs. 100." (1680)

Failure to provide education facilities to children of displaced persons

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Rehabilitation' be reduced by Rs. 100." (1683)

Failure to rehabilitate displaced persons in various Camps in West Bengal

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Rehabilitation' be reduced by Rs. 100." (1684)

Failure to provide proper marketing facilities for the goods produced by the Training Centres in West Bengal

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Rehabilitation' be reduced by Rs. 100." (1685)

Failure to develop cottage industries in various Townships and Colonies of displaced persons in West Bengal

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Rehabilitation' be reduced by Rs. 100." (1686)

Difficulties of the displaced persons of Rabindranagar Colony, Chandranagore to get medical relief.

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Rehabilitation' be reduced by Rs. 100." (1687)

Grievances of displaced persons of Tumeh Camp in Hoogly District regarding education of children

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Rehabilitation' be reduced by Rs. 100." (1688)

Failure to stop eviction of displaced persons in Mikir Hills

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Rehabilitation' be reduced by Rs. 100." (1707)

Early closure of displaced persons' camps in Orissa

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Rehabilitation' be reduced by Rs. 100." (1708)

Failure to rehabilitate displaced persons in Bihar

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Rehabilitation' be reduced by Rs. 100." (1709)

Need for representation of the West Bengal Government in the Dandakaranya Development Authority

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Rehabilitation' be reduced by Rs. 100." (1710)

Need for representation of Andhra Government in the Dandakaranya Development Authority

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Rehabilitation' be reduced by Rs. 100." (1711)

Need for arrangement of irrigation facilities in Dandakaranya

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Rehabilitation' be reduced by Rs. 100." (1712)

Need for adequate arrangement of drinking water in Dandakaranya

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Rehabilitation' be reduced by Rs. 100." (1713)

Need for replacing tents of displaced persons' camps in Dandakaranya by huts

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Rehabilitation' be reduced by Rs. 100." (1714)

Inadequate number of tractors for reclamation and cultivation works in Dandakaranya.

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Rehabilitation' be reduced by Rs. 100." (1715)

Irregularities in the allotment of contracts in Dandakaranya

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Rehabilitation' be reduced by Rs. 100." (1716)

Inadequacy of roads in Dandakaranya

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Rehabilitation' be reduced by Rs. 100." (1717)

Failure of normal agricultural production in reclaimed lands of Dandakaranya

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Rehabilitation' be reduced by Rs. 100." (1718)

Stoppage of maintenance grants to displaced persons in Dandakaranya

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Rehabilitation' be reduced by Rs. 100." (1719)

Working of the Dandakaranya Administration

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Rehabilitation' be reduced by Rs. 100." (1720)

Absence of educational facilities in Dandakaranya

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Rehabilitation' be reduced by Rs. 100." (1721)

Absence of medical facilities in Dandakaranya

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Rehabilitation' be reduced by Rs. 100." (1722)

Failure to make announcement regarding the title of the displaced persons to their allotted lands in Dandakaranya

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Rehabilitation' be reduced by Rs. 100." (1723)

Failure to give assurance regarding the fixation of rent on 'Khas lands' Dandakaranya

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Rehabilitation' be reduced by Rs. 100." (1724)

Stoppage of educational help to the displaced students in West Bengal

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head 'Expenditure on Displaced Persons and Minorities' be reduced by Rs. 100." (1725)

Irregularities in the distribution of loans to East Bengal displaced persons

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head 'Expenditure on Displaced Persons and Minorities' be reduced by Rs. 100." (1726)

Failure to improve the sanitary conditions of the displaced persons camps in West Bengal

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head 'Expenditure on Displaced Persons and Minorities' be reduced by Rs. 100." (1727)

Hardships faced by displaced persons due to the findings of the Screening Committee

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head 'Expenditure on Displaced Persons and Minorities' be reduced by Rs. 100." (1728)

Inadequate amount sanctioned for house-building loans

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head 'Expenditure on displaced persons and minorities' be reduced by Rs. 100." (1729)

Closure of displaced persons' camps in West Bengal

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head 'Expenditure on Displaced Persons and Minorities' be reduced by Rs. 100." (1730)

Stoppage of doles to displaced persons

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head 'Expenditure on Displaced Persons and Minorities' be reduced by Rs. 100." (1731)

Need to regularise displaced person's colonies of West Bengal

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head 'Expenditure on Displaced Persons and Minorities' be reduced by Rs. 100." (1732)

Need for re-introducing the Bainapatia Scheme in West Bengal

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head 'Expenditure on Displaced Persons and Minorities' be reduced by Rs. 100." (1733)

Need for reclamation of waste lands in West Bengal for displaced persons

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head 'Expenditure on Displaced Persons and Minorities' be reduced by Rs. 100." (1734)

Need to absorb displaced persons in West Bengal in industries

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head 'Expenditure on Displaced Persons and Minorities' be reduced by Rs. 100." (1735)

Failure of the Dandakaranya Scheme

Shri Assar: I beg to move:

"That the demand under the head 'Expenditure on Displaced Persons and Minorities' be reduced by Rs. 100." (1731)

Failure to give employment to all displaced persons

Shri Assar: I beg to move:

"That the demand under the head 'Expenditure on Displaced Persons and Minorities' be reduced by Rs. 100." (1767)

Failure to give proper medical facilities to displaced persons in various colonies

Shri Assar: I beg to move:

"That the demand under the head 'Expenditure on Displaced Persons and Minorities' be reduced by Rs. 100." (1767)

Need to develop cottage and home industries in various townships and colonies of displaced persons

Shri Assar: I beg to move:

"That the demand under the head 'Expenditure on Displaced Persons and Minorities' be reduced by Rs. 100." (1769)

Difficulties and grievances of the displaced persons from Chambur and Ulhasnagar regarding sanitation water and medical facilities

Shri Assar: I beg to move:

"That the demand under the head 'Expenditure on Displaced Persons and Minorities' be reduced by Rs. 100." (1770)

Irregularities in giving contracts in Dandakaranya

Shri Assar: I beg to move:

"That the demand under the head 'Expenditure on Displaced Persons and Minorities' be reduced by Rs. 100." (1771)

Failure to fulfil targets of the Dandakaranya Scheme

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the demand under the head 'Capital outlay of the Ministry of Rehabilitation' be reduced by Rs. 100." (1689)

Failure to provide drinking water to displaced persons settled in Dandakaranya

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the demand under the head 'Capital outlay of the Ministry of Rehabilitation' be reduced by Rs. 100." (1690)

Working of the Dandakaranya Development Authority

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the demand under the head 'Capital outlay of the Ministry of Rehabilitation' be reduced by Rs. 100." (1691)

Failure to provide irrigation schemes for Dandakaranya

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the demand under the head 'Capital outlay of the Ministry of Rehabilitation' be reduced by Rs. 100." (1692)

Failure to provide agricultural facilities to displaced persons settled in Dandakaranya

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the demand under the head 'Capital outlay of the Ministry of Rehabilitation' be reduced by Rs. 100." (1693)

Failure of the schemes in Dandakaranya for rehabilitation of displaced persons from East Bengal

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the demand under the head 'Capital outlay of the Ministry of Rehabilitation' be reduced by Rs. 100." (1694)

Mr. Speaker: These cut motions are now before the House.

19.05 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, April 12, 1960/Chaitra 23, 1882 (Saka).